



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 197-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2018
(प्रथम अग्रहायण, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 85/के०अ० 67/1957/धा० 15 तथा 23ग/2018, दिनांक 22 नवम्बर, 2018 — हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टार्किंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	757-762
भाग IV	शुद्धि पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग – III

हरियाणा सरकार

खान तथा भू-विज्ञान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 नवम्बर, 2018

संख्या का०आ० 85/के०अ० 67/1957/धा० 15 तथा 23ग/2018.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) की धारा 15 की उपधारा (1) तथा धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण (संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिज स्टाकिंग, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 (जिन्हे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 55 में, उप-नियम (3) में,—

(क) खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(iii) आशय का पत्र धारक/संविदाकार/पट्टाधारक खनन संक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व या अनुमत अवधि, जो सामान्यतः आशय का पत्र जारी करने की तिथि से बारह मास से अनधिक न हो, की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, बोली प्रतिभूति की बकाया राशि अर्थात् वार्षिक बोली राशि के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर जमा करवाएगा :

परन्तु जहां आशय का पत्र धारक/संविदाकार/पट्टाधारक द्वारा अपने स्तर पर सभी कदम उठाए जाने के बावजूद वे उपरोक्त अनुसार अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित पर्यावरण समाशोधन और संचालन सहमति प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो ऐसे आशय का पत्र धारक/संविदाकार/पट्टाधारक, पहले से की गई कार्यवाही के ब्यौरे देते हुए उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पूर्व निदेशक को प्रस्तुत किए गए विशिष्ट आवेदन पर, निम्नलिखित अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर संविदा/पट्टा अवधि के प्रारम्भ के लिए पहले से अनुज्ञात समय से और अधिक अन्य बारह मास तक के अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं:—

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | अगले छह मास तक की अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर। |
| 2 | छह मास तक की दूसरी अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय के भुगतान पर। |

टिप्पण.— विस्तार केवल मास (मासों) में दिया जाएगा तथा मास से कम अवधि/उसके भाग के लिए किसी अनुरोध को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आशय का पत्र धारक/संविदाकार/पट्टाधारक प्रारम्भिक अनुमत अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व निदेशक को विस्तार की ऐसी अनुरोधित अवधि के लिए फीस की अग्रिम राशि सहित अग्रिम में समय का विस्तार मांगने के लिए आवेदन करेगा;” ;

(ख) खण्ड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(v) जहां कोई भी आशय का पत्र धारक उक्त उप-नियम (3) (iii) के अधीन यथा विहित बकाया पन्द्रह प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करने में असफल रहता है, और/या आशय का पत्र जारी होने के बाद करार निष्पादित करने में असफल रहता है, तो आशय का पत्र रद्द समझा जाएगा तथा ‘प्रारम्भिक बोली प्रतिभूति’ के प्रति उस द्वारा जमा करवाई गई दस प्रतिशत राशि जब्त समझी जाएगी;” ;

(ग) खण्ड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(vi) जहां आशय का पत्र धारक/संविदाकार/पट्टाधारक, मांग पर भुगतान न की गई बकाया पन्द्रह प्रतिशत राशि जमा करवाने में असफल रहता है तथा आशय का पत्र/संविदा/पट्टा उक्त खण्ड (v) के अनुसार रद्द किया गया है, तो ऐसे बोलीदाता को पांच वर्ष की अवधि के लिए किन्हीं पश्चात्पूर्ती बोलियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

टिप्पण.— किसी कम्पनी/हिस्सेदारी फर्म द्वारा उक्त राशि के भुगतान की चूक की दशा में, उक्त कम्पनी और इसके सभी प्रोत्साहक और निदेशक, ऐसी हिस्सेदारी फर्म और इसके सभी हिस्सेदारों को पांच वर्ष की अवधि के लिए वैयक्तिक रूप में या किसी कम्पनी/फर्म के रूप में किन्हीं पश्चात्कर्तृ बोलियों में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा ;”।

3. उक्त नियमों में, प्ररूप एम.एल.-1 में, भाग III में,—

(क) खण्ड 4 में, उपखण्ड (क) में, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(ii) वार्षिक बोली राशि का पन्द्रह प्रतिशत खनन संक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व या अनुमत अवधि, जो सामान्यतः आशय का पत्र जारी करने की तिथि से बारह मास से अनधिक न हो, की समाप्ति पर, जो भी पहले हो:

परन्तु जहां आशय का पत्र धारक/पट्टाधारक द्वारा अपने स्तर पर सभी कदम उठाए जाने के बावजूद वे उपरोक्त अनुसार अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित पर्यावरण समाशोधन और संचालन सहमति प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो ऐसे आशय का पत्र धारक/पट्टाधारक, पहले से की गई कार्यवाही के ब्यौरे देते हुए उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व निदेशक को प्रस्तुत किए गए विशिष्ट आवेदन पर, निम्नलिखित अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर पट्टा अवधि के प्रारम्भ के लिए पहले से अनुज्ञात समय से और अधिक अन्य बारह मास तक के अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं:—

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | अगले छह मास तक की अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर। |
| 2 | छह मास तक की दूसरी अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय के भुगतान पर। |

टिप्पण.— विस्तार केवल मास (मासों) में दिया जाएगा तथा मास से कम अवधि/उसके भाग के लिए किसी अनुरोध को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

आशय का पत्र धारक/पट्टाधारक को प्रारम्भिक अनुमत अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व निदेशक को विस्तार की ऐसी अनुरोधित अवधि के लिए फीस की अग्रिम राशि सहित अग्रिम में समय का विस्तार मांगने के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि पट्टा की प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनिवार्य भाटक की वृद्धि पर, पट्टाधारी अगले तीन वर्ष के ब्लाक के सम्बन्ध में एक वर्ष के लिए यथा लागू पुनरीक्षित वार्षिक अनिवार्य भाटक के पच्चीस प्रतिशत के बराबर इस प्रकार बढ़ाई प्रतिभूति राशि की शेष प्रतिभूति राशि जमा करवाएगा।”;

(ख) खण्ड 5 में, उपखण्ड (क) में, “जो बारह मास से अधिक न हो” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, प्ररूप एम.सी.-1 में, भाग III में,—

(क) खण्ड 2 में, उप-खण्ड क में, मद (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(ii) वार्षिक बोली राशि का पन्द्रह प्रतिशत खनन संक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व या अनुमत अवधि, जो सामान्यतः आशय का पत्र जारी करने की तिथि से बारह मास से अनधिक न हो, की समाप्ति पर, जो भी पहले हो:

परन्तु जहां संविदाकार द्वारा अपने स्तर पर सभी कदम उठाए जाने के बावजूद वे उपरोक्त अनुसार अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित पर्यावरण समाशोधन और संचालन सहमति प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो ऐसा संविदाकार पहले से की गई कार्यवाही के ब्यौरे देते हुए उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व निदेशक को प्रस्तुत किए गए विशिष्ट आवेदन पर, निम्नलिखित अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर संविदा अवधि के प्रारम्भ के लिए पहले से अनुज्ञात समय से और अधिक अन्य बारह मास तक के अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं:—

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | अगले छह मास तक की अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर। |
| 2 | छह मास तक की दूसरी अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय के भुगतान पर। |

टिप्पण.— विस्तार केवल मास (मासों) में दिया जाएगा तथा मास से कम अवधि/उसके भाग के लिए किसी अनुरोध को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

संविदाकार प्रारम्भिक अनुमत अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व निदेशक को विस्तार की ऐसी अनुरोधित अवधि के लिए फीस की अग्रिम राशि सहित अग्रिम में समय का विस्तार मांगने के लिए आवेदन करेगा:

परन्तु यह और कि संविदा की प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संविदा धन—राशि की वृद्धि पर, संविदाकार तीन वर्ष के आगामी ब्लॉक के सम्बन्ध में एक वर्ष के लिए यथा लागू पुनरीक्षित वार्षिक संविदा धन राशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर इस प्रकार बढ़ाई गई प्रतिभूति राशि की शेष प्रतिभूति राशि जमा करवाएगा”।

(ख) खण्ड 3 में, उपखण्ड (क) में, “जो बारह मास से अधिक न हो” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

5. उक्त नियमों में, प्ररूप एम.पी.एस-1 में, भाग III में,—

(क) खण्ड 2 में, उप-खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ii) वार्षिक बोली राशि का पन्द्रह प्रतिशत खनन संक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व या अनुमत अवधि, जो सामान्यतः आशय का पत्र जारी करने की तिथि से बारह मास से अनधिक न हो, की समाप्ति पर, जो भी पहले हो:

परन्तु जहां परमिटधारक द्वारा अपने स्तर पर सभी कदम उठाए जाने के बावजूद वे उपरोक्त अनुसार अनुमत अधिकतम अवधि के भीतर खनन संक्रियाएं प्रारम्भ करने के लिए अपेक्षित पर्यावरण समाशोधन और संचालन सहमति प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो ऐसा परमिटधारक पहले से की गई कार्यवाही के ब्यौरे देते हुए उपरोक्त वर्णित अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व निदेशक को प्रस्तुत किए गए विशिष्ट आवेदन पर, निम्नलिखित अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर परमिट अवधि के प्रारम्भ के लिए पहले से अनुज्ञात समय से और अधिक अन्य बारह मास तक के अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं:—

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | अगले छह मास तक की अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के एक प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय फीस के भुगतान पर। |
| 2 | छह मास तक की दूसरी अवधि के विस्तार हेतु | प्रत्येक मास की अनुरोधित विस्तार अवधि के लिए, वार्षिक बोली राशि के दो प्रतिशत प्रतिमास की दर से अप्रतिदाय के भुगतान पर। |

टिप्पण.— विस्तार केवल मास (मासों) में दिया जाएगा तथा मास से कम अवधि/उसके भाग के लिए किसी अनुरोध को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

परमिटधारक प्रारम्भिक अनुमत अवधि की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पूर्व निदेशक को विस्तार की ऐसी अनुरोधित अवधि के लिए फीस की अग्रिम राशि सहित अग्रिम में समय का विस्तार मांगने के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु यह और कि परमिट की प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर परमिट धन—राशि की वृद्धि पर, परमिटधारक तीन वर्ष के आगामी ब्लॉक के सम्बन्ध में एक वर्ष के लिए यथा लागू पुनरीक्षित वार्षिक परमिट धन—राशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर इस प्रकार बढ़ाई गई प्रतिभूति राशि की शेष प्रतिभूति राशि जमा करवाएगा”।

(ख) खण्ड 3 में, उपखण्ड (क) में, “जो बारह मास से अधिक न हो” शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

अपूर्व कुमार सिंह,
प्रधान सचिव, खान तथा भूविज्ञान विभाग,
हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 22nd November, 2018

No. S.O. 85/C.A. 67/1957/S. 15 and 23C/2018.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 and section 23C of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 (hereinafter called the said rules), in rule 55, in sub rule (3), -

(a) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iii) The letter of intent holder/contractor/ lessee shall deposit the balance amount of Bid Security i.e. equal to fifteen percent of the annual bid amount before the commencement of mining operations or before expiry of period allowed, which shall ordinarily not be more than twelve months, from the date of issuance of letter of intent, whichever is earlier:

Provided that where the letter of intent holder/contractor/lessee having taken all steps on his part, fails to obtain required environmental clearance and consent to operate for undertaking mining operations within the maximum period allowed as per above, such letter of intent holder/contractor/lessee on a specific application submitted to the Director, at least thirty days prior to the end of the period mentioned above, giving details of the action already taken may seek additional time up to another twelve months, over and above the time already allowed for commencement of the period of contract/lease, on payment of a non-refundable fee as per the following:-

1	Extension of further period up to six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of one percent per month of the annual bid for each month of requested extension period
2	Extension for a second period of upto six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of two percent per month of the annual bid for each month of requested extension period

Note.— Extension shall be allowed only in month (s) and any request for period less/part of the month shall be summarily rejected.

The letter of intent holder/contractor/lessee shall apply for seeking extension of time after initially allowed period, to the Director, atleast thirty days in advance along with advance amount of the fee for such requested period of extension;”;

(b) for clause (v) the following clause shall be substituted, namely:-

“(v) Wherever a letter of intent holder fails to deposit the balance fifteen percent amount towards security as prescribed under sub-rule (3)(iii) above, and/or fails to execute the agreement after the issue of letter of intent, the same shall be deemed to have been revoked and the ten percent amount deposited by him towards ‘initial bid security’ shall stand forfeited;”;

(c) for clause (vi) the following clause shall be substituted, namely:-

“(vi) Where the letter of intent holder/contractor/lessee fails to deposit the un-paid fifteen percent amount on demand and the letter of intent/contract/lease has been revoked as per clause (v) above, such bidder shall be debarred from participation in any subsequent bids for a period of five years.

Note.— In case of default by a company, the said company and all of its Promoter/s and Director/s, in case of Partnership Firm along with such firm all of its partners shall be debarred from participation whether individually or as partner/proprietor/director in a company in bids for a period of five years;”.

3. In the said rules, in Form ML-1, in part III,-

(a) in clause 4, in sub-clause (a), for item (ii) the following item shall be substituted, namely:-

“(ii) fifteen percent of the annual bid amount before commencement of mining operations or before the expiry of period allowed, which shall ordinarily be not more than twelve months from the date of issuance of letter of intent, whichever is earlier:

“Provided that where the letter of intent holder/lessee having taken all steps on his part, fails to obtain required environmental clearance and consent to operate for undertaking mining operations within the maximum period allowed as per above, such letter of intent holder/lessee on a specific application submitted to the Director, at least thirty days prior to the end of the period mentioned above, giving details of the action already taken may seek additional time up to another twelve months, over and above the time already allowed for commencement of the period of lease, on payment of a non-refundable fee as per the following:-

1	Extension of further period upto six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of one percent per month of the annual bid for each month of requested extension period
2	Extension for a second period of upto six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of two percent per month of the annual bid for each month of requested extension period

Note.— Extension shall be allowed only in month(s) and any request for period less/part of month shall be summarily rejected.

The letter of intent holder/lessee shall apply for seeking extension of time after initially allowed period, to the Director, atleast thirty days in advance along with advance amount of the fee for such requested period of extension:

Provided further that on enhancement of the deed rent after expiry of every three year period of lease, the lessee shall deposit the balance amount of security so as to upscale the security amount equal to twenty five percent of the revised annual deed rent as applicable for one year with respect to next block of three years”.

(b) In clause 5, in sub-clause (a), the words, figure and sign “which shall not be more than twelve months,” shall be omitted.

4. In the said rules, in Form MC-1, in part III,-

(a) in clause 2, in sub-clause (a), for item (ii) the following item shall be substituted, namely:-

“(ii) fifteen percent of the annual bid amount before commencement of mining operations or before the expiry of period allowed, which shall ordinarily be not more than twelve months from the date of issuance of letter of intent, whichever is earlier:

“Provided that where the letter of intent holder/contractor having taken all steps on his part, fails to obtain required environmental clearance and consent to operate for undertaking mining operations within the maximum period allowed as per above, such letter of intent holder/contractor on a specific application submitted to the Director, at least thirty days prior to the end of the period mentioned above, giving details of the action already taken may seek additional time up to another twelve months, over and above the time already allowed for commencement of the period of contract, on payment of a non-refundable fee as per the following:-

1	Extension of further period upto six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of one percent per month of the annual bid for each month of requested extension period
2	Extension for a second period of upto six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of two percent per month of the annual bid for each month of requested extension period

Note.— Extension shall be allowed only in month(s) and any request for period less/part of month shall be summarily rejected.

The letter of intent holder/contractor shall apply for seeking extension of time after initially allowed period, to the Director, atleast thirty days in advance along with advance amount of the fee for such requested period of extension:

Provided further that on enhancement of the contract money after expiry of every three year period of contract, the contractor shall deposit the balance amount of security so as to upscale the security amount equal to twenty five percent of the revised annual contract money as applicable for one year with respect to next block of three years”.

- (b) In clause 3, in sub-clause (a), the words, figure and sign “which shall not be more than twelve months,” shall be omitted.

5. In the said rules, in Form MPS-1, in part III,-

- (a) in clause 2, for sub-clause (ii), the following item shall be substituted, namely:-

“(ii) fifteen percent of the annual bid amount before commencement of mining operations or before the expiry of period allowed, which shall ordinarily be not more than twelve months from the date of issuance of Letter of Intent, whichever is earlier:

“Provided that where the permit holder having taken all steps on his part, fails to obtain required environmental clearance and consent to operate for undertaking mining operations within the maximum period allowed as per above, such letter of intent holder/permit holder on a specific application submitted to the Director, at least thirty days prior to the end of the period mentioned above, giving details of the action already taken may seek additional time up to another twelve months, over and above the time already allowed for commencement of the period of permit, on payment of a non-refundable fee as per the following:-

1	Extension of further period upto six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of one percent per month of the annual bid for each month of requested extension period
2	Extension for a second period of upto six months	On payment of a non-refundable fee at the rate of two percent per month of the annual bid for each month of requested extension period

Note.— Extension shall be allowed only in month(s) and any request for period less/part of month shall be summarily rejected.

The letter of intent holder/permit holder shall apply for seeking extension of time after initially allowed period, to the Director, atleast thirty days in advance along with advance amount of the fee for such requested period of extension:

Provided further that on enhancement of the permit money after expiry of every three year period of permit, the permit holder shall deposit the balance amount of security so as to upscale the security amount equal to twenty five percent of the revised annual permit money as applicable for one year with respect to next block of three years”.

- (b) in clause 3, in sub-clause (a), the words and sign “which shall not be more than twelve months,” shall be omitted.

A. K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Mines and Geology Department.